डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 मई, 2026, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2026

| वर्ष 69 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सरकार खरीदेगी दूध, पशुपालकों को दिलाएगी दूध का समुचित दाम : मुख्यमंत्री

किसान कल्याण वर्ष में पशुपालकों और दूध उत्पादकों का भी करेंगे कल्याण

किसानों की जमीन ली, तो देंगे चार गुना मुआवजा

ग्वालियर में खोला जाएगा पशुओं का वेलनेस सेंटर

पशु स्वास्थ्य केन्द्र का किया जाएगा उन्नयन

डबरा में बनेगा नया पशु चिकित्सालय

हितलाभ वितरित कर, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़ने का दिलाया संकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में हुए शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर बहुत पुण्य भूमि है, जहां प्राचीनकाल से गौवंश और गौपालन की समृद्ध परम्परा रही है। हम पशुपालन और डेयरी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार कर रहे हैं। दुग्ध व्यवसाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह सभी पशुपालकों के आर्थिक स्वावलंबन का मजबूत माध्यम है। हम प्रदेश के हर किसान और पशुपालक को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार डेयरी क्षेत्र में नवाचार करते हुए निवेश भी बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। निवेश आयेगा, तो इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हम हमारे युवाओं को गांवों में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी बेहतर संभावनाओं पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बने, यही हमारा लक्ष्य है। पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। हम अपने प्रयासों से मध्यप्रदेश को देश का मिल्क केपिटल बनाकर रहेंगे। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर प्रबंधन और सभी पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को मिल्क केपिटल बनाने में ग्वालियर बड़ी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए और सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क केपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर क्षेत्रीय पशुपालकों को अपने पशुधन के स्वास्थ्य एवं उपचार की स्थानीय स्तर पर सुविधा मुहैया कराने के लिए ग्वालियर में पशुओं का केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, ग्वालियर के पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केन्द्र का उन्नयन करने तथा डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में पशुपालकों को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की सफलता की कहानियों तथा पशुधन विकास पर केन्द्रित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

हर ब्लाक में बनाया जा रहा है एक-एक वृंदावन ग्राम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशुपालक प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार हैं। किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के समग्र कल्याण में भी कोई कसर नहीं रखेगी। गाय का हो या भैंस का, सरकार पशुपालकों से सारा का सारा दूध खरीदेगी और इन्हें दूध का समुचित दाम भी दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि सभी पशुपालक स्वस्थ और उच्च कोटि का पशुधन पालें। सरकार की डा. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना का अधिकतम लाभ उठायें। पशुपालकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश को पर्याप्त और बेहतर आहार मिले, इसके लिए दी जाने वाली सहायता राशि हमने 20 रूपए से बढ़ाकर 40 रूपए प्रति गौवंश कर दी है। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक-एक वृंदावन ग्राम बनाया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाई कदापि चिंता न करें। प्रदेश में कहीं भी, किसी भी विकास अधोसंरचना निर्माण के लिए यदि सरकार किसानों से उनकी जमीन लेगी, तो अब उन्हें चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश के विकास में सहयोगी किसानों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता है।

25 गायों की गौशाला खोलने वालों को भी सरकार दे रही 10 लाख रूपए सब्सिडी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और हर किसान, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक को आत्मनिर्भर बनाने में डेयरी सेक्टर एक मजबूत आधार है। हमारी सरकार दुग्ध उत्पादन एवं इसके जरिए स्वावलंबन को ग्रामीण विकास का प्रमुख स्तंभ बनाकर प्रदेश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का कोई विकल्प नहीं है। यह गौवंश के दूध का पुण्य-प्रताप ही है कि हमारा देश और प्रदेश तेजी से चहुमुंखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। गेहूं उपार्जन जारी है। सरकार गेहूं उत्पादक किसानों का दाना-दाना खरीदेगी। किसानों के घर में खुशहाली लाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। पशुपालकों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सरकार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। नई-नई गौशालाएं खोली जा रही हैं। मात्र 25 गायों की गौशाला खोलने वाले पशुपालक को भी हमारी सरकार 10 लाख रूपए प्रति यूनिट सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि दूध के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार दूध के बढ़ते दाम का सीधा लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश की सड़कों पर निराश्रित एवं आवारा पशुओं को समुचित स्थान अर्थात् गौशालाओं तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी गौशालाओं की स्थापना के लिए भी हम अनुदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार पशुओं के मौके पर ही समुचित इलाज के लिए प्रदेश में गौ-एंबुलेंस का संचालन भी किया जा रहा है। एक फोन करने पर गौ-एम्बुलेंस सीधे पशुपालक के घर पहुंच जाती है। यह गौवंश के प्रति हमारे सम्मान, आस्था और संवेदनशीलता का भी परिचायक है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

किसानों को MSP दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह का सख्त रुख, NAFED-NCCF को लक्ष्य आधारित खरीद के दिए निर्देश

किसान MSP से नीचे उपज बेचने को मजबूर न हो : उपार्जन समीक्षा बैठक में श्री शिवराज सिंह चौहान का कड़ा संदेश

उपार्जन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, 72 घंटे में भुगतान और जिला-स्तरीय लक्ष्य तय करने के श्री शिवराज सिंह ने दिए निर्देश

किसान हित सर्वोपरि: श्री शिवराज सिंह ने NAFED-NCCF से कहा- जहां दाम कम हों वहां तुरंत प्रभावी खरीद करें

दलहन-तिलहन मिशन को गति देने के लिए श्री शिवराज का एक्शन मोड, राज्यों की बाधाएं दूर कराने का भरोसा

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन, नई दिल्ली में NAFED और NCCF के साथ उपार्जन संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव MSP से नीचे हैं, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान को उसकीउपज का न्यायसंगत मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य में किसी भी स्तर की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में NAFED और NCCF की उपार्जन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपार्जन को केवल औपचारिक स्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि किसानों को MSP का लाभ दिलाने वाले मिशन मोड दायित्व के रूप में लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि बाजार में कीमतें MSP से नीचे चल रही हैं और फिर भी खरीद अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है तो यह स्थिति किसानों के हित में नहीं मानी जा सकती। मंत्री श्री चौहान ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एजेंसियां अपने-अपने जिलों और केंद्रों के स्तर पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। उन्होंने कहा कि राज्यवार आवंटन के साथ-साथ जिला-स्तर पर उत्पादन, संभावित आवक और 25 प्रतिशत खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ताकि उपार्जन का लक्ष्य वास्तविक जमीन पर हासिल हो सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन-तिलहन, विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी फसलों पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि जहां किसानों को MSP से कम दाम मिल रहे हैं, वहां खरीद में तेजी लाना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपार्जन केंद्रों की संख्या, खरीद क्षमता, जिला-स्तरीय बाधाएं, राज्य सरकारों के निर्देश, गुणवत्ता संबंधी स्थानीय समस्याएं और भुगतान व्यवस्था इन सभी पहलुओं की रोजाना निगरानी की जाए और जहां भी बाधा हो, उसका समाधान तत्काल केंद्रीय स्तर पर रखा जाए। मसूर उपार्जन की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने राज्यों में वास्तविक बाजार भाव की ताजा जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कीमतें MSP के आसपास या नीचे हैं, वहां खरीद तंत्र और अधिक चुस्त किया जाए।

श्री चौहान ने किसानों को समय पर भुगतान को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि भुगतान व्यवस्था को तेज, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए। समीक्षा में यह मुद्दा सामने आया कि किसानों को भुगतान में विलंब की शिकायतें हैं, जिस पर मंत्री ने 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त SOP तैयार करने और राज्यों से चर्चा कर इसे प्रभावी रूप से लागू करने को कहा।

बैठक में राज्य पोर्टलों और CNA पोर्टल के एकीकरण, भुगतान में देरी, बिहार में DBT व्यवस्था की कमी, गुजरात में भुगतान विलंब, महाराष्ट्र में डेटा लंबित रहने और आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त मात्रा के लिए आंकड़े प्राप्त होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य के निर्देश, प्रक्रियाएं या स्थानीय प्रशासनिक अड़चनें किसानों से खरीद में बाधा बन रही हैं तो केंद्र सरकार सक्रिय समन्वय के जरिए उनका समाधान सुनिश्चित करेगी।

श्री चौहान ने यह भी कहा कि दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सफल होगा, जब किसानों को यह भरोसा होगा कि जरूरत पड़ने पर उनकी उपज MSP पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा स्पष्ट है- किसान को संकट में नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें उचित मूल्य, त्वरित भुगतान और प्रभावी खरीद तंत्र के माध्यम से मजबूत समर्थन देना है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने NAFED और NCCF को निर्देशित किया कि वे उपार्जन को लेकर बेहतर काम करें, समस्याओं की सूची बनाकर समाधान सहित प्रस्तुत करें और शेष अवधि में खरीद प्रदर्शन में ठोस सुधार दिखाएं। उन्होंने कहा कि किसान हित में केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और उपार्जन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

अभी तक किसानों को उपार्जित गेहूँ का 10403.17 करोड़ रुपये हुआ भुगतान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गेहूँ उपार्जन की कर रहे सतत मॉनीटरिंग

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और सतत मॉनीटरिंग तथा उपार्जन केन्द्रों के औचक निरीक्षण के परिणामस्वरूप गेहूँ की उपार्जन प्रक्रिया सुगमता से जारी है। किसानों को समय पर उपार्जित गेहूँ का भुगतान हो रहा है। अभी तक किसानों को 10403.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। गेहूँ का उपार्जन 23 मई तक होगा।

9.38 लाख किसानों से 56.45 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 9 लाख 38 हजार किसानों से 56 लाख 45 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 तक कर दिया गया है। गेहूँ का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जाता है।

प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई तथा तौल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही एनआईसी सर्वर

की क्षमता एवं संख्या में वृद्धि कराई गई। खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा उपार्जन की मॉनीटरिंग की जा रही है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाए आदि की व्यवस्थाएँ की गई हैं। किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके, इस हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, नेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटोग्राफ्स भारत सरकार के PCSAP पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है।

किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ की भर्ती जूट बारदाने के साथ साथ PP/HDP बेग एवं जूट के एक भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जिससे उपार्जित गेहूँ का सुरक्षित भण्डारण किया जा सके।

मैं ट्रॉली में गेहूं लेकर आया था और मात्र 10 मिनट में मेरी ट्रॉली खाली हो गई। यहाँ पानी, बैठने और अन्य सभी सुविधाओं की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आराम से बैठ सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती।"- रामचरण अन्ना, ग्राम रामकोट

हमारी पंचायत में भी सायलो की व्यवस्था है। हम यहाँ ट्रॉली खाली कराने आए थे। यहाँ पानी, छाया और बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाहर और अंदर दोनों जगह किसान आराम से पानी पी सकते हैं। टेंट लगाए गए हैं और पेड़ों की छांव भी अच्छी है। अंदर बैठने और गार्डन जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

- गोपाल सिंह
ग्राम पंचायत मानपुरा

इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होगा ब्रिक्स कृषि कार्य समूह का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल

दो चरणों में होगा सम्मेलन, कृषि नवाचारों पर होगी वैश्विक चर्चा

भोपाल : केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 9 से 13 जून तक इंदौर के ग्रेंड शेरेटन होटल में होगा। पांच दिवसीय इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। शहर की स्वच्छता, हरियाली और सुंदरता अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। उन्होंने नगर निगम, पुलिस प्रशासन, पर्यटन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थलों, प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष साफ-सफाई, आकर्षक सजावट और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, पारंपरिक खान-पान और कृषि नवाचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। विदेशी प्रतिनिधियों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदेश भ्रमण और कृषि उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। एयरपोर्ट और होटलों पर अंग्रेजी, रूसी, तुर्की सहित विभिन्न भाषाओं के जानकार गाइड तैनात किए जाएं और उन्हें व्यवहार और आतिथ्य का पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेहमानों का स्वागत पगड़ी, तिलक और फूलमालाओं के साथ भारतीय परंपरा के अनुरूप गर्मजोशी से किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य एवं प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को शामिल करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की ब्रांडिंग में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलम्बिया, इंडोनेशिया सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के लगभग 68 प्रतिशत किसान इन देशों में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।

बैठक में जानकारी दी गई कि सम्मेलन दो चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण में 9 से 11 जून तक वरिष्ठ अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्मार्ट कृषि, कृषि अनुसंधान, कृषि व्यापार, किसान कल्याण तथा सतत विकास रणनीतियों जैसे विषयों पर तकनीकी चर्चा होगी। इसके बाद 12 एवं 13 जून को कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कृषि क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और नीति संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श होगा। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में कृषि आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री मधु वर्मा, श्री रमेश मेंदोला, श्रीमती मालिनी गौड़, श्रीमती उषा ठाकुर, श्री सुमित मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हर कदम पर किसानों की आय बढ़ाना और खेती की लागत घटाना ही हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' में कृषि विभाग ने अन्नदाता को अन्न से लेकर आय तक, परंपरा से लेकर तकनीक तक, हर मोर्चे पर सशक्त किया है। समर्थन मूल्य, भावांतर, श्रीअन्न प्रोत्साहन, भंडारण, डिजिटल व्यवस्था और कृषि यंत्रीकरण से प्रदेश का किसान अब लागत घटाकर, आय बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

राज्य शासन ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीदी के लिये स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 तक कर दी है और प्रदेशभर में गेहूं का उपार्जन जारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में चना एवं मसूर का उपार्जन 30 मार्च से 28 मई 2026 तक किया जा रहा है। उड़द प्रोत्साहन योजना वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रीष्मकालीन उड़द का रकबा बढ़ेगा।

भावांतर भुगतान योजना में 7.10 लाख पंजीकृत किसानों द्वारा 16.95 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय किया गया। समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की 1476 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सीधे किसानों के खातों में अंतरित की गई। सरसों में 1.5 लाख किसान पंजीकृत हैं और योजना संचालित है।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 1 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रमुख उत्पादक 15 जिलों के 3,894 किसानों से 2,829.92 मीट्रिक टन कोदो-कुटकी का उपार्जन किया गया। राज्य सरकार द्वारा क्रय मूल्य के अतिरिक्त 1000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से किसानों को दी जाएगी। इससे श्रीअन्न की मूल्य श्रृंखला विकसित होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

किसानों की उपज सुरक्षित रखने के लिए खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत 3.55 लाख मीट्रिक टन नई भंडारण क्षमता निर्मित की जा चुकी हैं। भंडार योजना-सामग्री में 15 लाख मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिनमें 11 लाख मीट्रिक टन का पंजीयन पूरा हो गया है। किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 50 कृषि उपज मंडियों में ग्रेडिंग-सॉर्टिंग एवं पैकेजिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है। किसान अपनी उपज की ग्रेडिंग-सॉर्टिंग तथा पैकेजिंग निःशुल्क करा सकेंगे, जिससे मूल्य संवर्धन होगा।

ई-विकास प्रणाली के जरिए किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस डिजिटल व्यवस्था से लंबी कतारें, कालाबाजारी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। 01 अप्रैल 2026 से सभी जिलों में ई-किसान प्रणाली लागू है। किसान रजिस्ट्री से हर किसान को विशिष्ट पहचान और खेत की रजिस्ट्री से हर खेत की जियो-टैगिंग की जा रही है, जिससे फसल बीमा, ड्रोन छिड़काव और नुकसान का आंकलन आसान हुआ है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 3 लाख एकड़ में जैविक-प्राकृतिक खेती कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश के 56 कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी सहायता दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिये एक हजार से अधिक जैव संसाधन केंद्र और तीन हजार से अधिक कृषि सखी कार्यरत हैं। 200 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों को संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

किसानों के हित में समर्पित होकर कार्य करें कृषि कर्मयोगी : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड प्रारंभ, पैक्स समितियों में सदस्यता वृद्धि महाअभियान का भी हुआ शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुरू की किसानों के लिए टोल फ्री - 155253 सीएम किसान हेल्पलाइन

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के दौरान सोलह विभाग समन्वित रूप से किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। यह एक समग्र पहल है, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों को जोड़कर किसानों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला से प्रदेश में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी किसानों के समर्पण भाव के साथ नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाते हुए कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026 कृषक कल्याण के लिए समर्पित किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रवींद्र भवन, भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय वृद्धि के उद्देश्य से कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की शुरूआत की गई, जिनमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, पैक्स समितियों में सदस्यता वृद्धि महाअभियान और सीएम किसान हेल्पलाइन शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेल्पलाइन से जुड़कर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की और इसकी उपयोगिता का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की सेवा के लिए सीएम किसान हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। किसान भाई टोल फ्री नम्बर 155253 के माध्यम से इस नवाचारी पहल का लाभ ले सकेंगे। इस हेल्पलाइन से किसानों को त्वरित मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्मुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित सभी कृषि कर्मयोगियों से किसान हितैषी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पवित्र और समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के लिए कार्य करते हुए नए प्रयोगों के साथ अपने मन के नए अंकुरण और कोमलता को जीवंत रखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से पशुपालन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने कई असंभव कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाया है। प्रदेश में दुग्ध क्रांति हो रही है। वर्तमान में किसानों को प्रति लीटर दूध पर पहले की तुलना में 7 से 8 रुपए तक अधिक मूल्य मिल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अब व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे है। पहले रबी फसल वर्षा पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। नहरों और विद्युत सुविधाओं के विस्तार से खेत-खेत तक सिंचाई पहुंच गई है। इसके परिणामस्वरूप किसान अब वर्ष में 2 के स्थान पर 3 फसलें लेने लगे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस वर्ष राज्य सरकार किसानों से 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं उपार्जित कर रही है। राज्य सरकार ने उड़द की फसल पर समर्थन मूल्य के साथ देने की शुरुआत की है।

किसानों की अतिरिक्त आय का साधन बना एग्री वेस्ट मैनेजमेंट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान अब एग्री वेस्ट मैनेजमेंट अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। मक्के के डंठल, गेहूं और धान की नरवाई से भूसा बनाकर किसान लाभ कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों और नवाचारों के माध्यम से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। इजरायल में सीमित संसाधनों के बावजूद वहां खेती को अत्यंत आधुनिक और लाभकारी बनाया गया है। इजरायल में कम बारिश के बाद भी खेती में तकनीक का उपयोग प्रेरणास्पद है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार के लिए सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों बराबर हैं। कृषक परिवारों से आने वाले युवा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन खेती को भी लाभ का जरिया बनाया जा सकता है। इसके लिए युवाओं को प्रेरित करने की आवश्यकता है।

पीकेसी परियोजना के लिए हमारी सरकार के आभारी है राजस्थानवासी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को तीन-तीन नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगात मिली है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना से मध्यप्रदेश और राजस्थान के कई जिले लाभान्वित होने वाले हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार ने लागत की 90 प्रतिशत राशि दी है। पीकेसी परियोजना पर सहमति के लिए राजस्थान के 15 जिलों के लोग मध्यप्रदेश सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। मध्यप्रदेश नदियों का मायका है और यहां जलराशी का पर्याप्त भंडार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मां नर्मदा के आशीर्वाद से अपने गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गुजरात को विकसित और अग्रणी राज्य बनाया। अब हमारी सरकार भी नर्मदा के जल से प्रदेश को समृद्ध बना रही है। आज पानी की बूंद-बूंद को बचाकर खेती-किसानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि हर जिले में कृषि मेले आयोजित किये जा रहे हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से कृषि कर्मयोगियों के साथ मंथन हो रहा है। राज्य में किसान हितैषी सरकार है, मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसानों की परेशानियों के लिए चिंतित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री

श्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा है। इस कार्य में सभी कृषि कर्मयोगियों को सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सचिव कृषि श्री निशांत वरवड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोकसेवकों को कर्मयोगी की संज्ञा दी है। कृषक कल्याण वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन से आज सभी 55 जिले, विकासखंड, क्लस्टर लेवल और ग्राम पंचायतों से कृषि से जुड़े 16 विभागों के 1627 चुनिंदा अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला में आमंत्रित किया है। इसमें कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, मार्केटिंग फेडरेशन, बीज निगम, कृषि अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य विभाग शामिल हैं। कार्यशाला में किसानों की समस्याओं को बिना देरी के हल करने और किसान हेल्पलाइन की शुरुआत होगी। कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला में अलग-अलग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यशाला में पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री लखन पटेल, प्रशासक अपेक्स बैंक श्री महेंद्र सिंह यादव, प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव श्री श्री डीपी आहूजा, संचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विकास श्री उमाशंकर भार्गव सहित संपूर्ण प्रदेश से आए अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

महासंघ की कार्यप्रणाली को बनाये गतिशील एवं परिणामोन्मुख : राज्यमंत्री श्री पंवार

भोपाल : मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित की 114वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक मछुआ एवं मत्स्य कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में महासंघ की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी, गतिशील एवं परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया गया। राज्यमंत्री श्री पंवार ने अधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि मत्स्य क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। प्रमुख सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, प्रबंध संचालक श्री अनुराग चौधरी, डायरेक्टर श्री मनोज कुमार पथरोलिया सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 की नींव : मुख्यमंत्री

सच्चा वादा, पक्का काम के संकल्प के साथ किसानों से किए वादे पूरे कर रही सरकार

गेहूं की 2625 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जारी

कृषि यंत्रीकरण, मिट्टी परीक्षण व कृषक प्रोन्नति योजना से किसानों को मिल रहा दोहरा लाभ

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट विजन 'सच्चा वादा और पक्का काम' के अनुरूप प्रदेश सरकार किसानों से किए गए हर संकल्प को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट कहा है कि 'मध्यप्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सच्चा वादा और पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने किसानों से जो वादा किया, वह पूरा करके भी दिखाया है।' किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस मंशा को विभाग हर योजना में आत्मसात कर रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस से किसानों को सीधा लाभ

किसानों से किए वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की है। वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था। राज्य सरकार ने उस पर 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया, इस प्रकार 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की गई थी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस अलग से दिया जा रहा है। इस प्रकार इस वर्ष प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीदी कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 रुपये अधिक है। उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और किसानों के खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना शुरू की गई है। इसके तहत धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

यंत्रीकरण और वैज्ञानिक खेती से बढ़ रही किसानों की आय : कृषि मंत्री श्री कंषाना

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि कृषि उत्पादन की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सुपर सीडर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, बीज-उर्वरक ड्रिल आदि कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश के 2,500 कस्टम हायरिंग सेंटर से किसान किराए पर मशीनें ले रहे हैं। साथ ही बेहतर फसल उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य के लिए एवं संतुलित पौध पोषण के लिए विभाग निःशुल्क मिट्टी परीक्षण कर रहा है। मिट्टी परीक्षण से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर व सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है, जिससे किसान संतुलित मात्रा में उर्वरक डालकर लागत घटा सकते हैं। जायद सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज भंडारित किए गए हैं और मूंग-उड़द बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। रायजोबियम कल्चर सभी विकासखंडों में निःशुल्क उपलब्ध है।

किसानों को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली और 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' योजना में ड्रिप-स्प्रिंकलर पर 55 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। पात्र किसानों को सोलर पंप 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जायद फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है और नुकसान होने पर 72 घंटे में सर्वे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मक्का, बाजरा, सोयाबीन की उन्नत किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मक्का की एच.एम.-10, एच.क्यू.पी.एम.-1 जैसी 50 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता वाली किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि जायद सीजन में मूंग, उड़द, मक्का, सूरजमुखी जैसी फसलों को बढ़ावा देकर किसान 60 से 70 दिन में अतिरिक्त आय ले सकते हैं। दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ा रही हैं। विभाग द्वारा 'कृषि चौपाल' व 'किसान पाठशाला' के माध्यम से हर गांव तक तकनीकी मार्गदर्शन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि नरवाई न जलाएं और उसे खेत में मिलाकर जायद की बुवाई करें। ई-कृषि यंत्र अनुदान के लिए www.mpkrishi.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूँ उपार्जन केन्द्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण

खरगोन जिले के कतरगांव और शाजापुर के ग्राम मकोड़ी के गेहूँ उपार्जन केंद्र का किया औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने कतरगांव के कृषक श्री पाटीदार को सौंपी अनाज खरीदी पावती

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खरगोन जिले में मंडलेश्वर तहसील के कतरगांव और शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में गेहूँ उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और मंडी सचिव को निर्देशित किया कि गेहूँ उपार्जन से संबधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे निरंतर आकस्मिक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कतरगांव में कृषक श्री सुरेश पाटीदार की 55 क्विंटल गेहूँ की खरीदी के बाद ई-उपार्जन पोर्टल पर श्री पाटीदार को प्राप्ति ऑनलाइन जनरेट करवाई और कृषक को भुगतान राशि 1 लाख 44 हजार 374 रूपये का प्राप्ति पत्र सौंपा।

निर्देशों का पालन करें सुनिश्चित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महेश्वर में रात्रि विश्राम के बाद खरगोन जिले में कतरगांव गेंहूँ उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और मंडी सचिव को निर्देशित किया कि उपार्जन/खरीदी केंद्रों पर पूरे 6 तौल कांटे लगाए जाएं। सभी 6 तौल कांटों पर निरंतर तुलाई कार्य चलता रहे। गेहूं खरीदी के आज से नए मापदंड जारी हुए है वह लागू हो जाएं। किसानों के लिए उपार्जन/खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त छाया और शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक अन्नदाता को सम्मान और सुविधा के साथ उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए। किसानों की उपज की तुलाई समय पर हो सके इसके लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने, तौल कांटे, सिलाई मशीन, स्लॉट बुकिंग हेतु कंप्यूटर, नेट कनेक्शन, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि व्यवस्थाएं उपार्जन केन्द्र पर हमेशा उपलब्ध रहें। उन्होंने उपार्जन केंद्र पर कृषकों की सुविधा के लिए पेयजल, टेंट, बैठक, इत्यादि व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए।

किसानों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपार्जन केन्द्र कतरगांव में किसान व पशुपालक श्री भागीरथ मालवीय तथा अन्य किसानों से संवाद भी किया। किसानों तथा पशुपालकों से चर्चा कर उनके साथ चाय पी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहाँ स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्थायें और किसानों को ओटीपी के माध्यम से किये जा रहे भुगतान की जानकारी प्राप्त की। किसानों से शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अन्नदाता को सम्मान, सुविधा एवं उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनसे खेती-किसानी सम्बंधी चर्चा कर पशुपालन व डेयरी विकास के साथ ही परिजन के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान महेश्वर विधायक श्री राजकुमार मेव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मकोड़ी में ट्रॉली पर चढ़कर देखी उपज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में श्यामा गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहाँ स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्था और किसानों को ओटीपी के माध्यम से किये जा रहे भुगतान की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपार्जन केंद्र पर किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने ट्रैक्टर-ट्राली पर चढ़कर किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषक श्री दीपक, श्री राहुल से उनकी गेहूं की उपज की जानकारी ली और अन्य कृषकों से भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों को बताया कि उपार्जन अवधि 9 मई 2026 से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर उपार्जन अवधि को आगे भी बढ़ाया जाएगा। चिंता न करें उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। हमारी सरकार सभी किसानों के साथ खड़ी हैं।

आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसानों से उपार्जन स्थल पर पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पेयजल, छाया आदि के बारे में जानकारी ली गई और उपार्जन स्थल पर गेहूं के वजन की मात्रा को अपने समक्ष तुलवाकर भी देखा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मकोड़ी किसानों की संख्या, खरीदी एवं परिवहन की मात्रा तथा भुगतान की राशि आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बारदानों पर छपाई कर रही स्व-सहायता समूह की महिला श्रीमती संगीता बाई से छपाई के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना और शासन की अन्य योजनाओं से मिलने वाली राशि के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराजसिंह सिसोदिया, विधायक श्री अरुण भीमावद, डॉ. रवि पांडे, उज्जैन संभाग आयुक्त श्री आशीष सिंह, आईजी श्री राकेश कुमार गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत भसीन, शाजापुर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना, पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत मौजूद थे।

मसाला फसलों के उत्पादन में हम अव्वल, उद्यानिकी फसलों का करें विस्तार : डॉ. यादव

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्यानिकी फसलें छोटी जगह से बड़ी कमाई करने का प्रभावी माध्यम है। प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को इससे जोड़ा जाये। किसानों को सीज़नल और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग कर जैविक खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उद्यानिकी फसलों के माध्यम से किसानों की वास्तविक आय बढ़ाई जाए। किसानों की आय वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से उद्यानिकी फसलों और इनके जोत रकबे का साल-दर-साल विस्तार किया

फोटो दें....

जाए। उन्होंने कहा कि हमारी उद्यानिकी एवं मसाला फसलों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। इसकी पूर्ति के लिए बाजार तलाशें, उद्यानिकी उत्पादों की भरपूर ब्रांडिग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां औषधीय गुणों से भरपूर फसलों की खेती भी बहुतायत में की जाती है। इनकी बड़ी संभावनाएँ है। औषधि निर्माण के लिए जरूरी इन फसलों की इन्टरनेशनल मार्केट में मांग अनुसार आपूर्ति के लिए पूरी सप्लाई चेन तैयार की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में हर साल नये-नये आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल खोले जा रहे हैं। इनमें देशी/आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति में प्रदेश की औषधीय फसलों एवं उप-उत्पादों का भरपूर उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि मसाला फसलों के उत्पादन में हम पूरे देश में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि हमें इस क्षेत्र में और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय संचालित योजनाओं की प्रगति और हितग्राहियों को लाभ प्रदाय पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ - 2028 के मद्देनजर उज्जैन में फूलों की खेती को प्रोत्साहन एवं विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्लोरीकल्चर की स्थापना की जा रही है। सेंटर स्थापना के लिए उज्जैन शहर के पास एक गांव में 19 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर समुचित समन्वय भी किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया गया कि वर्ष 2030 तक उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। बागवानी फसलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिएप्रदेश में हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करने की कार्रवाई जारी है।

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों को दुनिया में पहचाना जाएगा। इसके लिए जी आई टैग दिलवाने की प्रक्रिया जारी है। विशेष रूप से जबलपुरी मटर, गुना का कुंभराज धनिया, बुरहानपुर का केला, रतलाम का रियावन लहसुन, खरगोन की मिर्च, इंदौर का मालवी आलू, बरमन भटा, छतरपुर का पान जैसे उद्यानिकी उत्पादों को जल्दी ही विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिल जाएगी।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मखाना क्षेत्र विस्तार योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों यथा नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, रीवा, शहडोल, रायसेन, अनूपपुर, पन्ना एवं सतना में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मखाना उत्पादन का रकबा इस वर्ष बढ़ाकर 85.00 हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा मखाना उत्पादन की कुल परियोजना लागत (एक इकाई) पर 40 प्रतिशत तक की अनुदान सहायता दी जाती है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इसी वर्ष जून माह में भोपाल में आम महोत्सव, जुलाई में खरगौन में मिर्च महोत्सव, सितम्बर में बुरहानपुर में केला महोत्सव, अक्टूबर में इंदौर में सब्जी महोत्सव, नवम्बर में ग्वालियर में अमरूद महोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही दिसंबर में ग्वालियर में मधुमक्खी पालन व्यवसाय के प्रोत्साहन एवं जागरूकता के लिए एक कार्यशाला/सेमिनार भी आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को संतरा महोत्सव भी आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम महोत्सव के दौरान प्रदेश के सभी 10 संभागों में आम के 10 बाग लगाने के प्रयास किए जाएं। केला महोत्सव में केले के तने से रेशे बनाने वाले उद्यमियों/उद्योगपतियों को जोड़ा जाये। सब्जी महोत्सव के दौरान नागरिकों को अपने घरों में किचन गार्डन लगाने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में प्रेसराईज इरीगेशन वाले जिलों में 15 हज़ार हैक्टेयर रकबे में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र का विस्तार भी किया जा रहा है। दो स्मार्ट बीज फार्म का विकास, सागर में झिला फार्म एवं देवास में कन्नौद फार्म विकसित किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग के अधीन 40 नर्सरियों का उन्नयन कर इन्हें पूरी तरह से हाईटेक किया जा रहा है। धार जिले के बदनावर के समीप रूपाखेड़ा गांव में युवाओं द्वारा फूलों की खेती की जा रही है। यह गांव मध्यप्रदेश में स्विट्जरलैंड के किसी गांव की तरह फूलों की खेती में विशेष पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां उद्यानिकी फसलों के लिए बेहद अनुकूल हैं, इसका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्रवार विशेष फसलों की पहचान कर किसानों को उनकी खेती के लिए प्रोत्साहित करें। उद्यानिकी फसलों के रकबे में तेजी से वृद्धि के लिए किसानों को जोड़कर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और बाजार उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उद्यानिकी क्षेत्र में ठोस और परिणामोन्मुखी कदम उठाए जाएं। पारम्परिक खेती के साथ-साथ किसानों को फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसी फसलों से जोड़ना जरूरी है, जो उन्हें त्वरित और अधिक नकद आय प्रदान कर सकें। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए किसानों को जोड़कर सभी उपाय किये जायें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाकर इन्हें और प्रभावी बनायें।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सरकार खरीदेगी दूध, पशुपालकों को दिलाएगी ....

10 हजार से अधिक गौवंश पाल रही लाल टिपारा आदर्श गौशाला

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर जिला हमारे लिए शुभंकर है। यहां 68 हज़ार 737 पशुपालक हैं। इनके द्वारा 4 लाख से अधिक पशुधन की सेवा की जा रही है। जिले में 605 मीट्रिक टन से अधिक प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां स्थापित प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपारा आदर्श गौशाला पंचगव्य का जिक्र करते हुए कहा कि यह गौशाला आत्मनिर्भरता की जीवंत मिसाल है। इसमें 10 हजार से अधिक गौवंश हैं। यहां प्रतिदिन 100 टन से अधिक गोबर से 25 टन जैविक उर्वरक और 2 टन सीएनजी का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि घाटीगांव के श्री कृष्णायन देशी गौ-रक्षा गौशाला में 2 हजार से अधिक गौवंश हैं। भितरवार के ग्राम तोड़ा और जुझारपुर की श्रीकृष्ण गौशालाओं में 800 से अधिक गौवंश से गौ-काष्ठ, जैविक खाद, दुग्ध और घी का उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर जिले ने कृषि क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत यहां 25 क्लस्टरों के जरिए 3 हजार 125 किसान प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन की शुरुआत गो माता का पूजन कर की । इसके उपरांत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वृन्दावन ग्राम थीम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौ-पूजन के उपरांत वृन्दावन ग्राम थीम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में लगभग 22 स्टॉल लगाए गए, जिनमें पशुपालन विभाग द्वारा आत्मनिर्भर गौशालाएं, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, क्षीर धारा ग्राम योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान तथा सहकार से समृद्धि अंतर्गत दुग्ध उत्पादों की लैब टेस्टिंग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान, कृषि यांत्रिकी विभाग द्वारा फसल अपशिष्ट प्रबंधन, मत्स्य विभाग ,मछुआ कल्याण, कृषि, चिकित्सा एवं उद्यानिकी विभागों द्वारा भी शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक एवं जानकारीपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई।

गौ-शालाओं से करीब हम पाल रहे 5 लाख से अधिक गौवंश

पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों का इतना वृहद समागम हुआ है। यह समागम डेयरी सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी प्रदेश में पशुपालन और डेयरी उद्यमिता को एक लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक से जुड़े 'रोजगार सृजन मॉडल' के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में 9 लाख लीटर प्रतिदिन कलेक्शन होता था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर काम करने पर अब यह कलेक्शन 12 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। हमारी सरकार इस दूध के इस कलेक्शन को 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नस्ल सुधार, गौशालाओं को हाइटेक और स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। क्षीरसागर योजना, हिरण्यगर्भा योजना और डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना के जरिए हम डेयरी सेक्टर के विकास में नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। स्वावलंबी गौशालाओं का निर्माण कर निराश्रित एवं आवारा पशुओं को इनमें आश्रय दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दो साल पहले तक प्रदेश में करीब 1800 गौशालाएं हुआ करती थीं। गौवंश सहायता राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश करने के बाद प्रदेश में 1300 नई गौशालाओं का निर्माण हुआ है। इन सभी गौशालाओं के माध्यम से करीब 5 लाख से अधिक गौवंश पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4156 आदर्श ग्रामों के जरिए पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण, हराचारा उत्पादन एवं नस्ल सुधार को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से सरकार की योजनाओं से जुड़कर प्रदेश और खुद के विकास के लिए आगे आने की अपील की।

सम्मेलन में जल संसाधन एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के संयोजक श्री महेंद्र सिंह यादव, म.प्र. वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत, म.प्र. कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष श्री बघेल, श्री लाल सिंह आर्य, श्री मोहन सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्वालियर जिले एवं संभाग से आए पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, किसान बंधु एवं हितग्राही उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने लद्दाख में विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन किया

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लद्दाख के लेह में केन्द्रशासित प्रदेश के लिए विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए सहकारिता मॉडल के तहत आज लद्दाख में ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज करगिल जैसी ऊंची जगह पर 10 टीएलपीडी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास हुआ है, जिसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है। करगिल की महिलाएं डेयरी प्लांट के माध्यम से अपने जीवन में उजाला ला सकती हैं, परिवार की मदद कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। श्री शाह ने कहा कि वे एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ की महिलाओं ने ऐसी ही छोटी-छोटी डेयरियों के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इतनी संभावना है कि यहां की महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई में योगदान कर सकें। श्री शाह ने कहा कि 25 करोड़ की लागत से जिस नई परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, वह निश्चित रूप से करगिल की माताओं-बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि लेह में पहले से काम कर रहे मिल्क प्लांट में प्रतिदिन उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में आईटीबीपी और सेना बहुत बड़े खरीददार हैं। यहां सीमा पर 18,000 जवान रहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आईटीबीपी और सेना की दूध, दही और पनीर की जरूरत इस प्लांट से पूरी होगी। श्री शाह ने कहा कि 45 लाख रुपए की लागत से एक मोबाइल प्रयोगशाला भी लॉन्च की गई है, जिससे दूध की क्वालिटी के रखरखाव में बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड आधारित AMCS ऐप का शुभारंभ भी हुआ है, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादक पशुपालक पारदर्शिता के साथ अपने दूध का हिसाब-किताब एक ही ऐप पर देख पाएंगे। इससे दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के मन में आत्मविश्वास भी जागृत होगा। उन्होंने कहा कि आज जिन पाँच पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया वे करगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी ने एक समझौता किया है। इससे लद्दाख को देश के बाजार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख के ऑर्गेनिक उत्पादों को दिल्ली का बड़ा बाजार मिलना चाहिए। श्री शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से आग्रह किया कि वह इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड को साथ लेकर एक त्रिपक्षीय एमओयू करें। उन्होंने कहा कि मदर डेयरी के प्रोडक्ट तो यहां बेचे ही जाएं, साथ ही मदर डेयरी अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यहां के प्रोडक्ट की भी देश भर में मार्केटिंग की व्यवस्था करे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम लद्दाख में डेयरी अवसंरचना का विस्तार करने जा रहे हैं। लेह में आने वाले दिनों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वह लेह में बढ़ने वाली संभावनाओं का तो दोहन करेगा ही, साथ ही करगिल में लगाए जा रहे संयंत्र से दूध बढ़ने पर दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहां के मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गाय और भैंस उपलब्ध कराने का काम होगा। लगभग हर साल अच्छी नस्ल की 500 गाय और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है, यहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए रिसर्च करके यहाँ के मौसम में ढल सकने वाले पशु स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि आगामी 10 साल में पशुओं की संख्या में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी करने की योजना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और एनडीडीबी में समझौता होने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हैं। उन्होंने एनडीडीबी के अध्यक्ष से कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में, जहां पशुपालन संभव हो, वहां एनडीडीबी की पहुँच होनी चाहिए और उन्हें इन सभी पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यहाँ दैनिक दूध की खरीद लगभग 7000 किलोलीटर तक पहुंची है। इसे अगले चार साल में 21,000 किलोलीटर तक पहुंचाकर यहां के किसानों की समृद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज एक डेयरी प्लांट का उन्नयन और पुनरुद्धार भी किया गया। पांच टीएलडीपी से बढ़ाकर इसकी क्षमता 10 टीएलडीपी कर दी गई साथ ही सेना के साथ एमओयू से इसे निश्चित रूप से फायदा होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है।पशुपालन विभाग में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2014-15 में भारत का कुल दूध उत्पादन 146 मिलियन टन था। आजादी से लेकर 2014-15 तक मतलब 70 साल में 146 मिलियन टन हुआ और 2014-15 से लेकर 2024-25 तक 146 मिलियन टन से बढ़कर 248 मिलियन टन हो गया। मतलब 70% वृद्धि केवल 10 साल में हुई और उसमें से 50% वृद्धि पिछले 5 साल में हुई है।उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2013-14 में 307 ग्राम थी, जो अब 485 ग्राम हो गई है।

उन्होंने कहा कि देश भर में कुल 2,36,000 सहकारी समितियों और लगभग 2 करोड़ दूध उत्पादकों के माध्यम से भारत ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 75,000 नई दूध समितियां बनाने का लक्ष्य रखा हैऔर 46,000 मौजूदा समितियों को आधुनिक व सक्षम बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 75,000 में से 21,000 नई समितियां बनाने का काम हो चुका है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख के प्रशासन से आग्रह है कि लद्दाख के हर गांव, जहां दूध उत्पादन और पशुपालन की संभावना है, का दोहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पश्मीना, ऑर्गेनिक उत्पादों और शहद से संबंधित सहकारी संस्थाओं को भी सहकारिता विभागआने वाले दिनों में जमीन पर उतारेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि लेह-लद्दाख और करगिल की बहुत पुरानी मांग थी कि इसे केन्द्र शासित प्रदेश(UT) बनाया जाए। UT बनाने की मांग का मूल कारण था कि यहां विकास नहीं होता था। गृह मंत्री ने कहा कि 2019 में लद्दाख को UT बनाने के बाद अब सात जिले और 193 पंचायतें हो गई हैं। पांच नए जिले — शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास — हाल ही में अधिसूचित हुए हैं। यहां की स्थानीय भाषा को भी प्रशासन की भाषा बनाया गया है। भोगी, पुर्गी, ऊर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले इस UT में 1,800 किलोमीटर सड़कें थीं, आज 4,040 किलोमीटर हो गई हैं। 19 पुल थे, आज 72 पुल बन चुके हैं। मोबाइल टावर 344 थे, आज 653 हो गए हैं। हेलीपैड 7 थे, आज 41 हो गए हैं। बर्फ हटाने वाली मशीनें पहले 7 थीं, आज 215 हैं। ग्रिड से जुड़े गांव 145 थे, आज 184 हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पहले 1,182 थे, आज 3,153 हो गए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का फोकस लद्दाख पर रहा है और यहाँ ढेर सारे विकास के काम हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि जोजिला दर्रा साल में 127 दिन बंद रहता था, इस बार सिर्फ 19 दिन बंद रहा। कारगिल-जांस्कर मार्ग 154 दिन बंद रहता था, वह सिर्फ 11 दिन बंद रहा। बर्फ हटाने वाली मशीनों और अन्य संरचनाओं के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है।जोजिला सुरंग का काम प्रगति पर है और सिंकुला सुरंग का काम शुरू हो चुका है। नया नागरिक हवाई अड्डा भी बनने का काम चालू हो गया है। VSAT कनेक्टिविटी सभी पंचायतों में कर दी गई है और 4G टावरों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण काम भी हुआ है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। 174 आईसीटी लैबस्थापित किए गए हैं और 230 स्मार्ट क्लास भी बनाए गए हैं। 40 खगोल विज्ञान लैब बनाई गई हैं। 24 अटल टिंकरिंग लैब बनी हैं और लद्दाख 2024 में पूर्ण साक्षर बनने वाला प्रशासनिक यूनिट बन गया है। यहां अब कोई अनपढ़ नहीं है।हर घर जल योजना में लगभग 98% घरों को कनेक्ट किया गया है। कृषि और बागवानी के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन विकास के कामों के साथ यहां के लोगों को सहकारिता और नए अवसरों को भी स्वीकारना पड़ेगा, तभी हम काम को आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख का बजट लगभग 6,000 करोड़ रुपए हो चुका है। लद्दाख जब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, तब मात्र 1,000 करोड़ रुपए खर्च होता था। आज भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की है, जो औद्योगिक विकास के लिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।हम चाहते हैं कि यह सीमांत प्रदेश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि वह लद्दाख और करगिल के वासियों का धन्यवाद करते हैं। भारत पर जब-जब इस सीमा से संकट आया, लद्दाख वालों ने अपने सीने पर गोली खाई और देश की रक्षा की। श्री शाह ने कहा कि भारत स्काउट का इतिहास कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक पूरा देश जानता है।लद्दाख के लोगों की देशभक्ति, देश की सुरक्षा और इस बहुत बड़े भू-भाग को भारत के साथ जोड़े रखने की तत्परता — भारत का हर नागरिक इसकी प्रशंसा करता है और भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुएलद्दाख के लोगों के प्रति कृतज्ञ भी है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सदस्यता अभियान को ग्राम भींगावा में मिला व्यापक जनसमर्थन

दादाजी कृषक उत्पादक संगठन द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों ने दिखाई उत्साहपूर्ण भागीदारी

भोपाल। ग्राम भींगावा, जिला खंडवा में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा किसान उत्पादक संगठन (FPO) सदस्यता अभियान के अंतर्गत दादाजी कृषक उत्पादक संगठन, मलगांव द्वारा किसान जागरूकता एवं सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 100 किसानों एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए किसान उत्पादक संगठन की सदस्यता एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति गहरी रुचि व्यक्त की।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को किसान उत्पादक संगठन (FPO) से जोड़ना तथा उन्हें सामूहिक कृषि व्यवसाय, आधुनिक कृषि प्रबंधन, विपणन व्यवस्था एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। सम्मेलन में किसानों को बताया गया कि वर्तमान समय में छोटे एवं सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एफपीओ एक मजबूत एवं प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। कार्यक्रम में किसानों को जानकारी दी गई कि एफपीओ से जुड़कर किसान सामूहिक रूप से उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ एवं अन्य कृषि आदान सामग्री कम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के सामूहिक संग्रहण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत में कमी होने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि संभव हो सकेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से पधारे डिप्टी डायरेक्टर श्री गौरव शाक्य ने किसानों को सहकारिता आधारित व्यवसाय मॉडल एवं किसान उत्पादक संगठनों की उपयोगिता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसान संगठित होकर सामूहिक रूप से कार्य करें, तो वे कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं, वित्तीय सहायता, इक्विटी ग्रांट एवं व्यवसायिक गतिविधियों से मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक किसानों को एफपीओ से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट श्री संतोष कुमार येड़े ने किसानों को सदस्यता अभियान के महत्व एवं किसान एकजुटता की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "एफपीओकेवलएकसंस्थानहीं, बल्कि किसानों की सामूहिक ताकत है। जब किसान एक मंच पर आकर कार्य करते हैं, तब वे बाजार की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं।"

उन्होंने किसानों को सामूहिक विपणन, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एफपीओ के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा गांव की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

कार्यक्रम में लेखा एक्सपर्ट श्री रॉबिन सक्सेना एवं श्री मनीष राजपूत द्वारा किसानों को एफपीओ की वित्तीय गतिविधियों, शेयर पूंजी, लाभांश वितरण, व्यवसाय संचालन एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि संगठन की मजबूत वित्तीय संरचना एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली से सदस्य किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

इस अवसर पर दादाजी कृषक उत्पादक संगठन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), लेखापाल, संचालक मंडल सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में एफपीओ से जुड़कर सामूहिक विकास एवं आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की दिशा में आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सदस्यता अभियान का स्वागत किया तथा एफपीओ के माध्यम से व्यवसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की। किसानों ने संगठन से जुड़कर सामूहिक शक्ति के माध्यम से कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देने का संकल्प लिया।

किसान जागरूकता कार्यक्रम में एफपीओ की योजनाओं एवं लाभों की दी गई विस्तृत जानकारी

भोपाल : ग्राम पंचायत शाहपुर में सांची किसान उत्पादक संगठन द्वारा किसान जागरूकता एवं सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को किसान उत्पादक संगठन (FPO) से जोड़ते हुए उन्हें सामूहिक खेती, कृषि व्यवसाय, बाजार प्रबंधन तथा शासन की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, महिला कृषकों एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा संगठन की सदस्यता ग्रहण करने में गहरी रुचि दिखाई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट श्री संतोष कुमार येड़े ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों की आर्थिक उन्नति एवं आत्मनिर्भरता के लिए किसान उत्पादक संगठन सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे एवं सीमांत किसान व्यक्तिगत रूप से बाजार में अपनी मजबूत पहचान स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन जब किसान संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से कार्य करते हैं, तब वे बड़े स्तर पर व्यवसाय स्थापित कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि "एफपीओकेवलएकसंस्थानहीं, बल्कि किसानों की सामूहिक शक्ति एवं आत्मनिर्भरता का मजबूत मंच है। जब किसान एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम बनते हैं तथा गांव स्तर पर रोजगार एवं विकास के नए अवसरों का सृजन होता है।"

श्री येड़े ने किसान उत्पादक संगठन की उपयोगिता, उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए बताया कि एफपीओ के माध्यम से किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं, इक्विटी ग्रांट, मार्जिन मनी सहायता, कृषि ऋण, प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों की आवश्यकताओं एवं स्थानीय उत्पादन क्षमता के आधार पर अनेक व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ कर सकता है।

उन्होंने जानकारी दी कि एफपीओ के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ एवं अन्य कृषि आदान सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। साथ ही कृषि उत्पादों के संग्रहण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन जैसी गतिविधियों को संगठित रूप से संचालित कर किसानों को बेहतर बाजार एवं उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करते हुए संगठन से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का आह्वान किया गया। किसानों ने भी एफपीओ की गतिविधियों एवं योजनाओं में विशेष रुचि व्यक्त करते हुए सदस्यता अभियान का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कई किसानों एवं महिला कृषकों ने संगठन से जुड़कर सामूहिक विकास की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर श्री भवानी जाटव (जनपद सदस्य), श्री मोहन किशोर (सरपंच), श्री लीला किशन (सचिव), सहसचिव श्री दिनेश कुमार, सांची किसान उत्पादक संगठन के संचालक मंडल सदस्य श्री प्रताप सिंह अहिरवार एवं श्री कुमेर सिंह राजपूत, संगठन के लेखापाल श्री योगेंद्र सिंह राजपूत, सीड संस्था के सीईओ श्री मनीष राजपूत, श्रीमती अंजू धानक सहित अनेक महिला कृषक एवं ग्रामीणजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।